

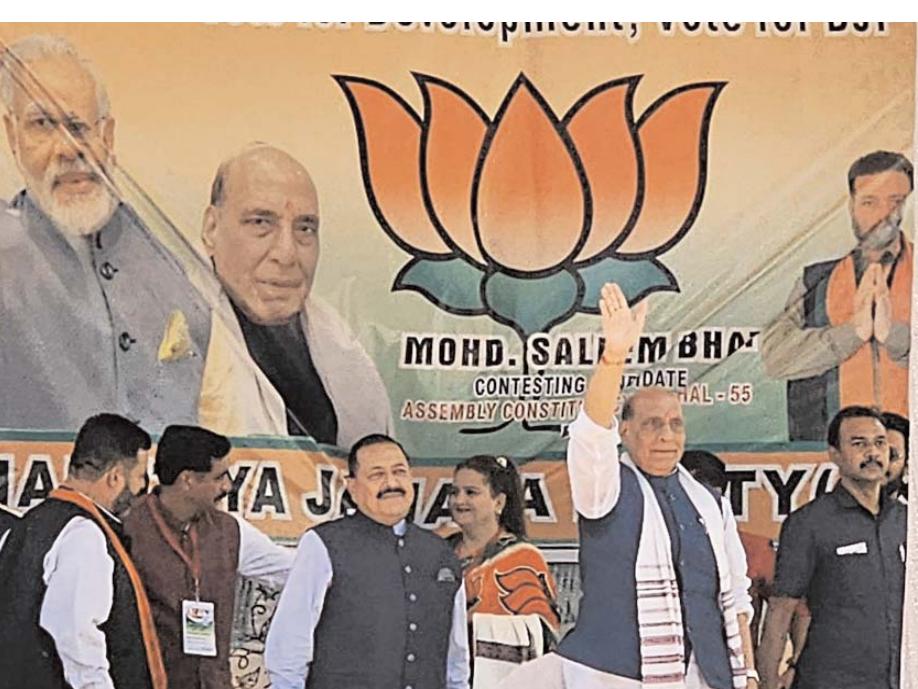
संपादकीय

घुटती सांसों से कम होती औसत आयु की चिन्ता

वायु प्रदूषण का संकट भारत की राष्ट्रव्यापी समस्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की हाल ही में जारी रिपोर्ट इस चिन्ता को बढ़ाती है जिसमें कहा गया कि वायु प्रदूषण के चलते भारत में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ रही है। जिसमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले पी.एम. 2.5 कण की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक मानकों से कहीं अधिक प्रदूषण भारत में लोगों की औसत आयु तीन से पांच वर्ष एवं दिल्ली में दस से बाहर वर्ष कम कर रहा है। बहरहाल प्रदूषण के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से मुहिम छेड़ने की जरूरत है। अध्ययन कहता है कि देश की एक अरब से अधिक आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहाँ प्रदूषण डब्ल्यूएचओ के मानकों से कहीं अधिक है। दरअसल, देश के बड़े शहर आबादी के बोझ से त्रस्त हैं। बढ़ती आबादी के लिये रोजगार बढ़ाने व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां लगायी गईं, उनकी भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका रही है। डीजल-पेट्रोल के निजी वाहनों को बढ़ता काफिला, निर्माण कार्यों में लापरवाही, कचरे का निस्तारण न होना और जीवाश्म ईंधन ने प्रदूषण बढ़ाया है। यह बढ़ता वायु प्रदूषण हमारी जीवन शैली से उपजे प्रदूषण की देन भी है। यह निराशाजनक खबरों के बीच उत्साहवर्धक खबर यह भी है कि भारत में सूक्ष्म कणों से पैदा होने वाले जानलेवा प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन अभी जीवन प्रत्याशा घटाने वाले प्रदूषण को लेकर जारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' बताती है कि भारत में साल 2021 की तुलना में 2022 के वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की कमी आई है। हालांकि, यह उपलब्ध मौजूदा हालात में बहुत बड़ी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यह बात उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इक्यावन दिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, हम अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन एक विश्वास जगा है कि युद्ध स्तर पर प्रयासों से भयावह प्रदूषण के खिलाफ किसी हद तक जंग जीती भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही सूचकांक-2024 में यह चेताया भी है कि यदि भारत में डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 के सांद्रता मानक के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी आने की आशंका पैदा हो सकती है।

जम्मू-कश्मीर पर रक्षामंत्री का दूरगामी सन्देश

कर रही हैं कि उन्हें भी इस ओर आजाद फिजा में सांस लेने का मौका मिले। ऐसे में रक्षामंत्री ने उन्हें भारत का हिस्सा बनने का निर्मत्रण देकर पड़ोसी देश की दुखती रग को छेड़ दिया है एवं पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, बल्कि गुलाम कश्मीर के लोगों में भी नया विश्वास एवं मनोबल जगा दिया है रक्षामंत्री का यह निर्मत्रण बहुत मायने रखता है, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि गुलाम कश्मीर हमारा है एवं हम इसे लेकर रहेंगे गुलाम कश्मीर के लोग भारत से मिलने के लिये उत्सुक हैं, आंदोलनरत हैं। क्योंकि पाकिस्तानी शासक उन्हें विदेशियों की तरह देखते हैं। यह एक सच्चाई भी है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का जैसा दमन और शोषण कर रहा है, उसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसी दमन और शोषण के चलते जब-तब वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उत्तरकर लोग भारत जाने की अनुमति भी मांगते रहते हैं। गुलाम कश्मीर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को मारा जा रहा है। वहाँ के लोग यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारतीय भूभाग में किस तरह तेजी से विकास हो रहा है और उन्हें किस तरह पाकिस्तान की ओर से टगा जाता रहा है। कहना कठिन है कि रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि वह आतंकवाद को सहयोग-समर्थन देने से बाज आएगा। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इस चुनाव पर सिर्फ भारतीयों नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुलाम कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी गुलाम कश्मीर के लोग हमारे ही



लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान ने कभी अपना माना ही
नहीं है। राजनाथ सिंह का गुलाम कश्मीर के लोगों
को संदेश पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील
की तरह है। रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य के जरिये
चुनाव के परिदृश्यों को एक नया मोड़ दिया है।
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को
भी निशाने पर लिया। उनके लिए ऐसा करना
इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि नेशनल
कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता पाकिस्तानपरस्ती का
परिचय देते हुए उससे बात करने पर जोर दे रहे हैं,

लेकिन ऐसा करते हुए वे यह रेखांकित नहीं करते कि वार्ता के लिए उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। नेशनल कॉफ़्नेस और पीडीपी कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद-370 की वापसी का भी सपना दिखा रहे हैं। यह दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं, व्यांकि अब इस विभाजनकारी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद की वापसी संभव नहीं और इसीलिए रामबन में राजनाथ सिंह ने कहा, भाजपा ने डंके की चोट पर अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर में शांति और करना बाहर का क्षण पर निरापद कानून का घोषणापत्र में किए गए वार्दों से सहमत है? उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उमर अब्दुल्ला के इस आकलन से सहमत है कि संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कुछ हासिल नहीं हुआ? यह अलगाववाद और आतंकवाद के दौर की वापसी के समर्थकों की हमदर्दी हासिल करने वाला ही बयान है और इसीलिए राजनाथ सिंह ने उन पर कठाक्ष किया कि अफजल को फांसी न दी जाती तो क्या उसके गले में हार डाले जाते।

कश्मीरी की सोच बताएंगे विधानसभा चुनाव

अशोक मधुप

जमू-कश्मीर विधानसभा लिए 18 सितंबर से एक अटूबर 2024 तक तीन चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे आठ अटूबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कश्मीर की जनता या चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जमूङ्कश्मीर में बड़ी तादाद में विकास हुआ। शांति लौटी। रोज की होने वाली पत्थरबाजी से जमू-कश्मीर की मुक्ति मिली। सिनेमा हाल खुल गए। पर्यटक आने लगे। मुहर्रम के जुलूस निकलने लगे। कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, इसके बावजूद देखना यह है कि कश्मीर का मतदाता या इस विकास



बाद जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई। इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सात जनवरी 2016 को निधन हो गया। राज्यपाल शासन लगा पर कम समय के लिए लगा। फिर महबूबा मुफ्ती ने वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए रूप में शपथ ली। पिछली राज्य सरकार से जून 2018 में भाजपा ने पीड़ीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया। नवंबर 2018 में, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य विधानसभा भंग कर दी। 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भाजपा की ओर से हाल ही में कंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी घोषणापत्र जारी किया। इसमें आतंकवाद के सफाए और हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास तक, भाजपा ने कई प्रमुख वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि यह क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्टी के वादों और योजनाओं के अनुरूप है। नए जम्मू और कश्मीर के लिए 25 वादों में से, भाजपा ने जम्मू और कश्मीर को

राष्ट्र के विकास और प्रगति में अग्रणी बनाने के लिए आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करने की कसम खाई। कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले की राजनीतिक स्थिति बहाल करने का भी वादा किया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोह-ए-मरान करने की बात कही है। इसे कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी की भावनाओं को भुनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के चुनाव के विभिन्न दलों के स्थानीय नेता तो चुनाव प्रचार में उत्तर ही चुके हैं। बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं की भी सभाएं शुरू हो गई हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है। रोड शो निकाले जा रहे हैं। घर-घर जाकर नेता लोगों से बोट मांग रहे हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर घाटी में परिवारवादी दलों के दिन अब खत्म नजर आ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढांचे के इस तरह विकास किया गया है कि पिछले दिनों श्रीनगर में जी-20 देशों की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भी श्रीनगर में ही आयोजित किया गया। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हालात तो ये बता रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है किंतु जम्मू-कश्मीर की बारामुला सीट लोकसभा सीट से आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख की जीत कुछ और ही इशारा कर रही है। उन्होंने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्लाह को दो लाख से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। बारामुला सीट पर रशीद को चार लाख 72 हजार बोट मिले जबकि उमर अब्दुल्लाह को दो लाख 68 हजार बोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन। उन्हें एक लाख 73 हजार बोट मिले। अब्दुल रशीद शेख के स्थानीय समर्थक अब्दुल माजिद इस जीत पर बीबीसी से कहते हैं कि साल 2019 के बाद जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, इंजीनियर रशीद की जीत उसी बात का जवाब है। उनका हक्क था कि कश्मीर के युवाओं ने जिस तरह इंजीनियर रशीद का समर्थन किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि नई पीढ़ी नए चेहरों को ढूँढ़ रही है और पारंपरिक राजनीति से तंग आ चुकी हैं। इंजीनियर रशीद को %आतंकवाद की फर्डिंग% के आरोप में यूएपीए के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। रशीद अबामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापकों में से एक है। 2019 में भी उन्होंने बारामुला से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उन्होंने बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ा था जेल जाने से पहले इंजीनियर रशीद शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर समस्या को हल करने की वकालत करते रहे हैं। इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के सख्त खलिफ थे और इस मुद्दे को लेकर वह सड़कों पर भी उतरे थे। उन्होंने इसके विरोध में कई धरने भी दिए हैं। सरकार का दावा है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर विकास कि राह पर आगे बढ़ रहा है और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी बार-बार %नए कश्मीर% की बात कर रहे हैं लेकिन कश्मीर में कुछ लोग इसे %जबरन खामोशी% भी कहते हैं। उनका आरोप है कि किसी को खुलकर बात करने नहीं दी जाती है। इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। देखिए क्या होता है। अमेरिका और मित्र देशों ने 20 साल अफगानिस्तान को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जमकर निवेश किया था, किंतु एक झटके में वह इस्लाम के रास्ते पर चला गया। यही डर है। अभी तो कश्मीर में फौज है। देखना यह है कि बिना फौज के भी कश्मीर का रूख ये ही रहता है, या वह फिर पुराने आतंकवाद के रास्ते पर लौटता है। हालांकि हम भारतीय आशावादी हैं। आशा करते हैं कि सब ठीक होगा। कश्मीरी नागरिक और युवा नए कश्मीर, विकसित कश्मीर को स्वीकार कर विकास का रास्ता अपनाएं।

